जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

https://cwc.gov.in/en/Jalansh

अंक.3

अक्टूबर-2024

खंड-07

प्रकाशन

जल संसाधन मूल्यांकन खंड-II

भारत में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का संग्रह

भारत में जलाशयों के अवसादन पर संग्रह 2024

जलाशय निगरानी

विषय सूची

पृष्ठ 1

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

- उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार एवं झारखण्ड
- सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर

पृष्ठ 2

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

- एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पृष्ठ 3

बांध सुरक्षा अधिनियम,2021/ एनडीएसए/ड्रिप

- डीआरआईपी चरण II और III की राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) की दूसरी बैठक

पृष्ठ 4

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- देश में बाढ़ की स्थिति - सितम्बर 2024

पृष्ठ 5

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- वार्ता समिति की 8वीं और 9वीं बैठक
- पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली पर संयुक्त समिति की छठी बैठक

पृष्ठ 6

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- तटस्थ विशेषज्ञों के साथ साझा किए जाने वाले डेटा पर चर्चा के लिए तकनीकी उप समिति की 18वीं बैठक
- 8वें भारत जल सप्ताह के दौरान के.ज.आ. के प्रकाशनों का विमोचन

पृष्ठ 7

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- के.ज.आ. के विभिन्न प्रकाशनों के लिए प्रमाण पत्र वितरण
- केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

पृष्ठ 8

आंतरिक हैकाथॉन 2024

पृष्ठ 9

जलाशय निगरानी

अध्यक्ष का संदेश

श्री राकेश कुमार वर्मा
अध्यक्ष, के.ज.आ

सितंबर 2024 भारत के जल संसाधन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति और सहयोगात्मक प्रयास देखे गए। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह ने "समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग" विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में वैश्विक और देशीय विशेषज्ञता का संगम देखने को मिला। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और आईसीआईडी जैसे प्रतिष्ठित संगठनों ने सतत जल प्रबंधन रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए हाथ मिलाया, जो एक न्यायसंगत और अनुकुल भविष्य के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में, उत्तरी कोयल परियोजना की 39वीं तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) की बैठक में डब्ल्यूआरडी बिहार द्वारा भूमि अधिग्रहण, डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति आदि पर चर्चा हुई। जबकि पेन्नैयार नदी जल विवाद पर 9वीं वार्ता समिति की बैठक में जटिल अंतर-राज्य जल मुद्दों को हल करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का प्रदर्शन किया गया। ये विचार-विमर्श जल प्रबंधन की बहुमुखी चुनौतियों से निपटने में संवाद और आम सहमति की शक्ति को रेखांकित करते हैं।

इस महीने का एक अन्य आकर्षण भारत जल सप्ताह के दौरान तीन प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन था:

- "जल संसाधनों के बेसिन वार मूल्यांकन पर अध्ययन" – यह एक व्यापक विश्लेषण है जो कुशल संसाधन प्रबंधन के लिए डेटा-संचालित पद्धति के महत्व को रेखांकित करता है।
- "भारत में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सार-संग्रह"- देश भर में सिंचाई परियोजनाओं के दायरे और पैमाने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला एक मूल्यवान संसाधन।
- "भारत में जलाशयों के अवसादन पर सार-संग्रह 2024"-जलाशयों में अवसादन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने वाला और उनकी परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़।

इसके अलावा, एनआईएच, रूड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, जल विज्ञान अनुसंधान में एक परिवर्तनकारी उछाल का प्रतीक है, जो नदी निगरानी और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है।

इस महीने की चार उपलब्धियों की एक और आधारशिला क्षमता निर्माण पहल थी। राष्ट्रीय जल अकादमी(एनडब्ल्यूए),पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने हितधारकों को जल संसाधन प्रबंधन के विविध क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस किया। आंतरिक हैकाथॉन 2024 नवाचार के लिए एक मंच के रूप में उभरा है, जो जल क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रस्तुत करता है।

जब हम इन उपलब्धियों पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे सामूहिक प्रयास राष्ट्र को एक टिकाऊ और समावेशी जल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, मैं अपने सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सक्रिय रूप से इसमें शामिल हों, अपने विचार साझा करें, तथा एक सुदृढ़ जल पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में योगदान दें। आइये, हम सब मिलकर इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाते रहें तथा एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें, जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का प्रबंधन समान और स्थायी रूप से किया जा सके।

राकेश

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

उत्तर कोयल परियोजना, बिहार और झारखंड के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीईसी की 39वीं बैठक

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 39वीं बैठक 10.09.2024 को के.ज.आ., नई दिल्ली में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग, के.ज.आ. मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और वैपकोस के अधिकारियों ने भाग लिया।

जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वैपकोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, बिहार भाग (आरडी 68.37 किमी से 109.09 किमी) में आरएमसी और इसकी संरचनाओं की लाइनिंग, मरम्मत और निर्माण के कार्य के लिए निविदा की स्थिति, झारखंड के दाएं मुख्य नहर के वितरण नेटवर्क (12 माइनर) के मिट्टी कार्य, मरम्मत और निर्माण के कार्य के लिए निविदा की स्थिति, बिहार में आरएमसी से वितरण प्रणाली के निर्माण के कार्य के लिए निविदा की स्थिति, आरएमसी से बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की स्थिति, झारखंड सरकार के पास शेष अप्रयुक्त राशि की वापसी की स्थिति आदि जैसे महत्वपूर्ण एजेंडा मदों पर चर्चा हुई ।

सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर के लिए विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति (ईपीआरसी) की छठी बैठक

सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर के पुनःअस्तरण कार्यों की देखरेख के लिए विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति (ईपीआरसी) की छठी बैठक श्री नवीन कुमार, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में 4 सितंबर, 2024 कोसेवा भवन, आरके पुरम, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई।

समिति के सदस्य, के.ज.आ. के अधिकारी, पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ईपीआरसी ने पुनःअस्तरण कार्यों की स्थिति, किसानों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विरोधों के कारण हुई देरी के कारणों की समीक्षा की। समिति ने पायलट कार्य के मूल्यांकन में तेजी लाने, दोनों फीडरों के शेष खंडों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देने और पुलों, रेगुलेटर आदि जैसे पक्के ढांचे के निर्माण सहित परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

जल संसाधन विभाग, पंजाब ने ईपीआरसी को 04.07.2024 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के अनुवर्ती कार्रवाई पर की गई प्रगति/कार्रवाई से अवगत कराया। बताया गया कि सभी तकनीकी पहलुओं और संभावित लोडिंग स्थितियों पर विचार करते हुए पायलट कार्य का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए के.ज.आ., सीएसएमआरएस, आईआईटी रुड़की और आईआईटी रोपड़ के विशेषज्ञों की एक समिति 30 जुलाई 2024 को गठित की गई है और समिति ने 13 अगस्त 2024 को पायलट कार्य स्थल का दौरा किया है। समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। इस संबंध में, ईपीआरसी ने पंजाब सरकार के अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पायलट कार्य के मूल्यांकन में तेजी लाएं।

रनगुवां बांध, छतरपुर (मध्य प्रदेश)

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	उद्देश्य
1	जल संसाधन प्रबंधन परसिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला	एक दिन	59	सिविल इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र
2	बांधों में यंत्रीकरण	पांच दिन	57	हाइड्रोलिक संरचनाओं में उपकरणों की आवश्यकता और महत्व, विभिन्न निगरानी तकनीकों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है
3	जल संसाधन क्षेत्र में पायथन प्रोग्रामिंग और अनुप्रयोग का परिचय	दो सप्ताह	850	पायथन प्रोग्रामिंग, ज्यूपिटर नोटबुक, पायथन में मूल डेटा प्रकार और डेटा संरचनाएं, फ़ंक्शन, लूप और नियंत्रण प्रवाह, पायथन में त्रुटि और फ़ाइल हैंडलिंग, पांडा और न्यूमपी के साथ कार्य करना, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, समय श्रृंखला विश्लेषण, भू-स्थानिक विश्लेषण और पायथन का उपयोग करके क्यूजीआईएस अनुकूलन का अवलोकन ।
4	भारत के जल संसाधन क्षेत्र का अवलोकन	चार दिन	61	महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के नवनियुक्त ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए

डीआरआईपी चरण II और III की राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) की दूसरी बैठक

बाहरी वित्त पोषित बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी-II) योजना के लिए 25 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में दूसरी राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल संसाधन विभाग, के.ज.आ., सीपीएमयू, विश्व बैंक, एआईआईबी, राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों और डीआरआईपी चरण-II के तहत शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, सभी अधिकारियों से प्रथम एनएलएससी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट, परियोजना की प्रगति, डीआरआईपी के अंतर्गत श्रेणी I और II बांधों को शामिल करना, एम.टेक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति और अन्य निर्धारित एजेंडे जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

सीपीएमयू-डीआरआईपी के परियोजना निदेशक श्री राकेश कश्यप के नेतृत्व में सीपीएमयू इकाई के सभी अधिकारियों ने भाग लिया और द्वितीय एनएलएससी बैठक के सफल आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया।

I. बाढ़ से संबंधित मामले

देश में बाढ़ की स्थिति - सितंबर 2024

ब्रह्मपुत्र ,बराक और झेलम बेसिन में 01.05.2023 को नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू हुई। 1 मई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान, कुल 9119 (6325 स्तर + 2794 अंतर्वाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 8661 (6044 स्तर + 2617 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 94.98% सटीकता के साथ स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। सितंबर 2024 के महीने के दौरान केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 212 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 120 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2024 से 30.09.2024 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

छह एफएफ स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्रमसं.	राज्य	ज़िला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	असम	जोरहाट	ब्रह्मपुत्र	नेमाटीघाट	30/06/2024	02/07/2024
2		सोनितपुर	जियाभराली	जिया-भाराली एनटी रोड क्रॉसिंग	01/07/2024	01/07/2024
3		शिवसागर	दिखो	शिवसागर	02/07/2024	02/07/2024
4		डिब्रूगढ़	बुरीडीहिंग	खोवांग	02/07/2024	03/07/2024
5	बिहार	सीतामढ़ी	बागमती	धेंग ब्रिज	28/09/2024	29/09/2024
6		मुजफ्फरपुर	बागमती	रुनीसैदपुर	29/09/2024	30/09/2024

66 बाढ़ निगरानी स्टेशन ने चरम बाढ़ की स्थिति देखी।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 87 बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

असम, बिहार, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में126 निगरानी केन्द्रों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, कर्नाटक और गुजरात में 49 बाढ़ नियंत्रण केंद्रों पर सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सीमा से अधिक अंतर्वाह वाले जलाशय

तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 77 जलाशयों में उनकी निर्धारित सीमा से अधिक अंतर्वाह प्राप्त हुआ।

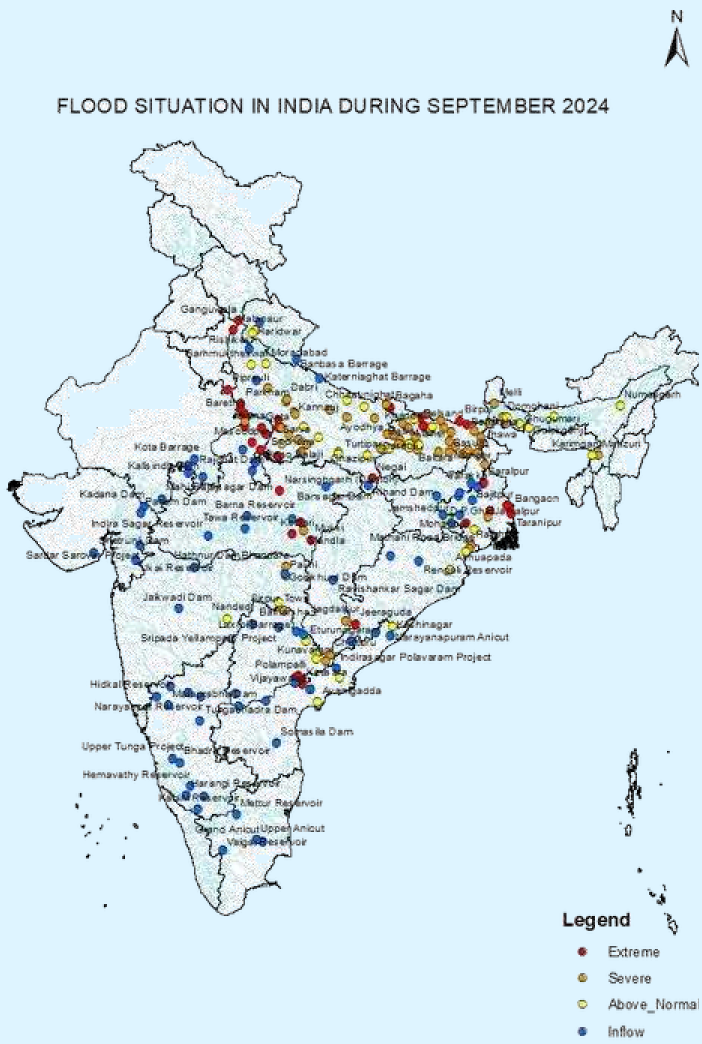

II. अंतर्राज्यीय विवाद

आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के तहत तमिलनाडु राज्य की शिकायत के संबंध में वार्ता समिति की 8वीं बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 20 सितंबर, 2024 कोपेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की 8वीं बैठक आयोजित की। बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अधिकारी, एनआईएच और केंद्रीय जल आयोग(मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

के.ज.आ.के अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों को बताया कि वार्ता समिति (भाग-1) की रिपोर्ट 19.09.2024 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को सौंप दी गई है। बैठक के दौरान, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य द्वारा किए गए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययनों पर विस्तार से चर्चा की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, के.ज.आ. के अध्यक्ष ने कुछ प्रस्ताव रखे, ताकि कर्नाटक के यारगोल बांध के निचले हिस्से में बेसिन में पानी की उपलब्धता के बारे में तमिलनाडु की चिंताओं को दूर किया जा सके। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों ने प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की।

पेन्नैयार मुद्दों पर शिकायत के संबंध में वार्ता समिति की 9वीं बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 28 सितंबर, 2024 कोपेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की 9वीं बैठक आयोजित की। बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, एनआईएच, रुड़की के अधिकारी और केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान, कर्नाटक के यारगोल बांध के निचले हिस्से में पानी की उपलब्धता के बारे में तमिलनाडु की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्नाटक राज्य ने कुछ संशोधनों के साथ सभी सुझाए गए प्रस्तावों पर सहमति जताई। हालांकि, तमिलनाडु के सदस्य ने इस संबंध में अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं। इसके बाद, बैठक के दौरान वार्ता समिति (भाग-2) की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

III. अन्य गतिविधियां

पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली पर संयुक्त समिति की छठी बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 3 सितंबर, 2024 कोपश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने हेतु एक संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए हाइब्रिड मोड में समिति की छठी बैठक आयोजित की।

बैठक में जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जीएफसीसी, एफबीपी, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनआरएससी, आईडब्ल्यूएआई, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सरकार और के.ज.आ. के अधिकारी शामिल हुए।

समिति की मसौदा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। 1डी और 2डी अध्ययनों के परिणामों के बारे में व्यापक चर्चा की गई। संवेदनशील क्षेत्रों और उठाए जाने वाले कदमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सुझावों के अनुसार मामूली संशोधनों के साथ मसौदा रिपोर्ट को समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

तटस्थ विशेषज्ञों के साथ साझा किए जाने वाले डेटा पर चर्चा के लिए तकनीकी उप समिति की 18वीं बैठक

भारत और पाकिस्तान के बीच आईडब्ल्यूटी मुद्दों पर मतभेदों को हल करने के लिए नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ की तीसरी बैठक 08-12 सितंबर, 2024 केदौरान ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई।

बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में श्री कुशविंदर वोहरा (अध्यक्ष, के.ज.आ.), श्री विवेक त्रिपाठी (मुख्य अभियंता), श्री नरेंद्र सिंह शेखावत (निदेशक) और श्री समर्थ अग्रवाल (निदेशक) शामिल थे। के.ज.आ. टीम का नेतृत्व के.ज.आ. के अध्यक्ष ने किया

विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि के अनुच्छेद IX के अंतर्गत तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति विशेष रूप से किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में दोनों देशों के बीच तकनीकी मतभेदों को दूर करने के लिए की गई थी।

8वें भारत जल सप्ताह के दौरान के.ज.आ. के प्रकाशनों का विमोचन

सुश्री देबाश्री मुखर्जी,सचिव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) और जल शक्ति मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री राज भूषण चौधरी,माननीय राज्य मंत्री,जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 19 सितंबर 2024 को 8वें भारत जल सप्ताह के समापन सत्र के दौरान भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग के तीन प्रकाशनों का विमोचन किया गया।

केंद्रीय जल आयोग ने "जल संसाधनों के बेसिन-वार आकलन पर अध्ययन" में रिमोट सेंसिंग अनुमानों का उपयोग करते हुए 1985-86 से 2022-23 तक की अवधि के लिए जल संसाधनों का बेसिन-वार आकलन पूरा कर लिया है। अध्ययन के अनुसार, भारत में पानी की उपलब्धता 2116 बीसीएम है। यह अध्ययन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों और प्राधिकरणों सहित सभी हितधारकों द्वारा जल संसाधनों की योजना और विकास के लिए उपयोगी होगा।

इसके अलावा, के.ज.आ. ने देश में पूरी हो चुकी और चल रही वृहत, मध्यम और ईआरएम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानकारी संकलित की है। "भारत में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संग्रह" केअनुसार, देश में 1323 पूर्ण हो चुकी वृहत /मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिनकी कुल संभावित सिंचाई क्षमता 47.62 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) है। इसके अलावा, 397 वृहत /मध्यम परियोजनाएँ क्रियान्वयन के अधीन हैं, जिनकी कुल अंतिम सिंचाई क्षमता 17.40 एमएचए है। यह संग्रह जल संसाधन परियोजनाओं की आगे की योजना बनाने, नीति निर्माण और सिंचाई उपयोग दक्षता में सुधार के लिए उपयोगी होगा।

इसके अतिरिक्त,के.ज.आ. ने अध्ययन पूरा कर लिया है और हाइड्रोग्राफिक तकनीक के साथ-साथ रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके 548 जलाशयों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए "भारत में जलाशयों के अवसादन पर सार-संग्रह 2024" नामक प्रकाशन तैयार किया है। अध्ययन के अनुसार, इन परियोजनाओं के सकल और सक्रिय भंडारण का औसत नुकसान क्रमशः 0.74% और 0.49% है। यह अध्ययन नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में किए गए मृदा संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के अलावा योजना स्तर पर ही अवसादन की दर के सही अनुमान और भंडारण के नुकसान का उचित अनुमान लगाने में उपयोगी है। प्रकाशन के पीडीएफ संस्करण के.ज.आ.वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

के.ज.आ. के विभिन्न प्रकाशनों के लिए प्रमाण पत्र वितरण

केंद्रीय जल आयोग द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशनों जैसे भारत के जल संसाधनों का आकलन, भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन, बाढ़ से होने वाले नुकसान के आंकड़ों पर रिपोर्ट, प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राष्ट्रीय रजिस्टर और भारत में जलाशयों के अवसादन पर सार-संग्रह के सफल संकलन में शामिल सभी अधिकारियों को प्रशंसा पत्र वितरित करने के लिए 30 सितंबर 2024 को सेवा भवन में एक समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने संबंधित अधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

प्रमुख जल विज्ञान अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की के बीच 27.09.2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, जल विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाना है।

केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की उपस्थिति में केन्द्रीय जल आयोग के पी एंड डीओ के मुख्य अभियंता श्री डी पी

मथुरिया और एनआईएच रुड़की के निदेशक श्री एम के गोयल ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ज्ञापन "एंट्रॉपी-आधारित गैर-संपर्क निर्वहन निगरानी तकनीक: भारतीय नदियों के लिए परीक्षण और कार्यान्वयन" नामक शोध परियोजना पर केंद्रित है। यह सहयोग कृष्णा और गोदावरी नदियों के पार पाँच स्थलों को कवर करेगा, जिसमें एनआईएच रुड़की उन्नत निगरानी प्रणालियों की स्थापना का नेतृत्व करेगा। इस साझेदारी से भारत की नदी प्रणालियों के लिए निर्वहन निगरानी, जल प्रबंधन और हाइड्रोलॉजिकल डेटा सटीकता में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आंतरिक हैकाथॉन 2024

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा के विजन और दिशा के अनुरूप, जुलाई 2024 में आंतरिक हैकथॉन 2024 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। हैकथॉन का उद्देश्य जल क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना और के.ज.आ. अधिकारियों की प्रतिभा का लाभ उठाना था।

संगठन के सभी इच्छुक अधिकारियों से नामांकन आमंत्रित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जल-संबंधी विषयों पर कुल छह नवीन प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। प्रस्तावित समाधानों की खूबियों का मूल्यांकन करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की एक स्क्रीनिंग समिति बनाई गई।

प्रारंभिक प्रदर्शनों के बाद, शीर्ष समाधानों को सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष की उपस्थिति में 14 सितंबर, 2024 को आयोजित अंतिम प्रस्तुति के लिए चुना गया था। शीर्ष दो प्रविष्टियाँ थीं:

1. डिज़ाइन मॉड्यूल
2.जलाशयों के क्षेत्र-क्षमता विश्लेषण के लिए वेब एप्लिकेशन

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

इन समाधानों को हैकाथॉन के सबसे आशाजनक और प्रभावशाली विचारों के रूप में मान्यता दी गई, जिन्होंने जल प्रबंधन क्षेत्र में मूल्यवान नवाचारों का योगदान दिया।

उर्मिल बांध, उत्तर प्रदेश

जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग देश के 155 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। 155 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 180.852 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 70.15% है।

केंद्रीय जल आयोग देश के 155 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। 155 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 180.852 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 70.15% है। इस प्रकार, 26.09.2024 बुलेटिन के अनुसार 155 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 121% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 113% है।

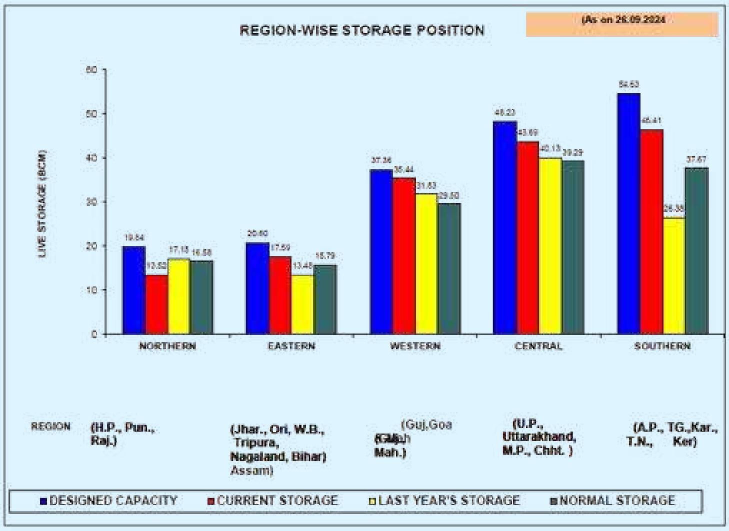

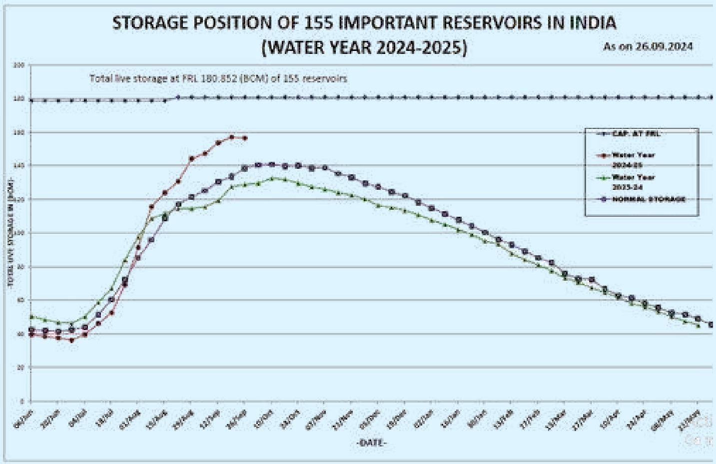

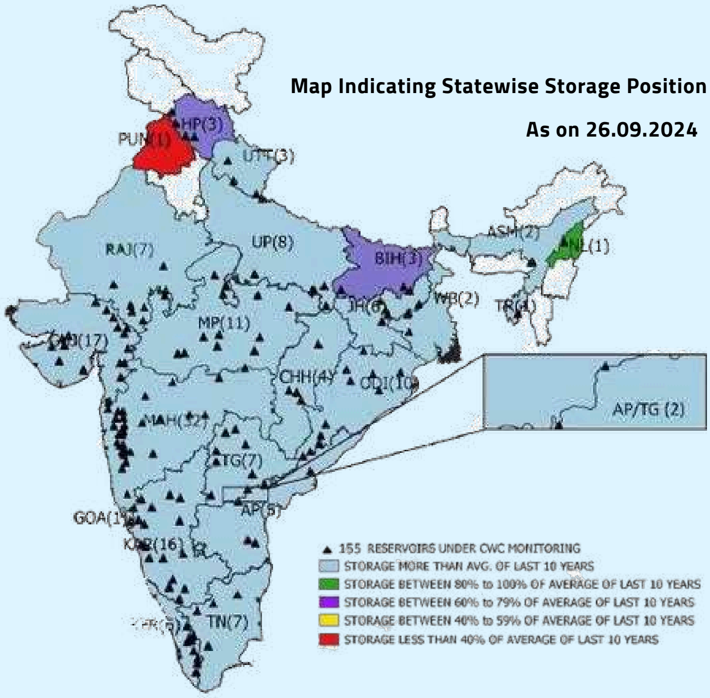

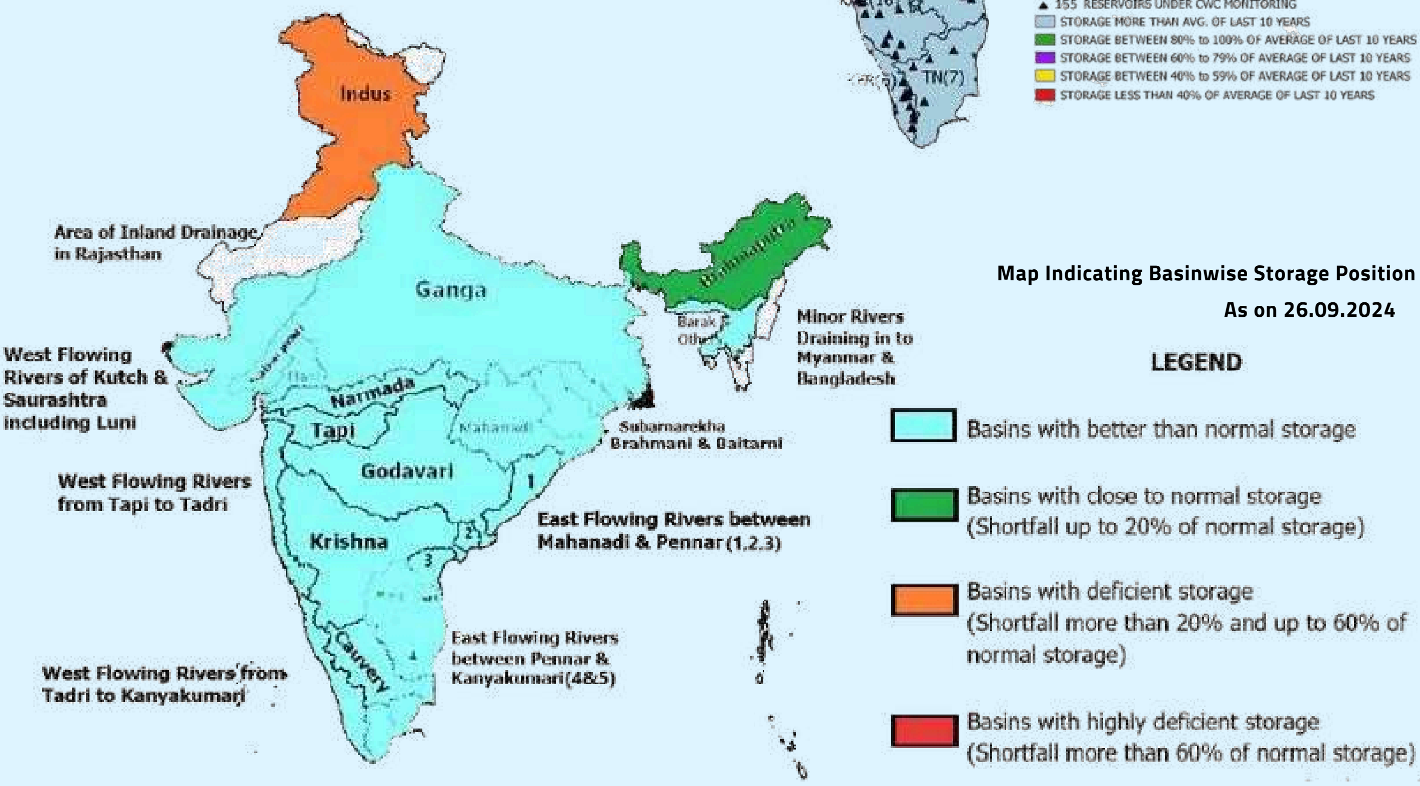

हिंदी पखवाड़ा आयोजन 2024

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा-2024 का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल आयोग में हिन्दी पखवाड़ा-2024 का आयोजन 14 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक किया गया। इस उपलक्ष्य में अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा एक अपील जारी की गई जिसमें के.ज.आ. (मुख्यालय) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने का निदेश दिया गया। इसके अलावा माननीय गृहमंत्री महोदय का संदेश भी परिचालित किया गया। हिंदी अनुभाग द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को हिन्दी पखवाड़ा-2024 के आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय महोदया के निदेशानुसार, हिंदी पखवाड़ा-2024 का उद्घाटन हिन्दी दिवस समारोह एवं चतुर्थ राजभाषा सम्मेलन के माध्यम से भारत मंडपम, नई दिल्ली से हुआ एवं समापन समारोह का आयोजन केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में किया गया। हिन्दी पखवाड़ा के दौरान सभी प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

हिंदी पखवाड़ा-2024 के तहत निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:-

1. हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता (हिंदी भाषी एवं हिन्दीत्तर भाषियों के लिए)
2. अनुवाद प्रतियोगिता (सभी के लिए)
3. निबंध प्रतियोगिता (सभी के लिए)
4. हिंदी टंकण प्रतियोगिता (कम्प्यूटर पर)
5. श्रुतलेख प्रतियोगिता (एमटीएस कर्मचारियों के लिए)
6. काव्य प्रतियोगिता (हिन्दी भाषियों एवं हिंदीत्तर भाषियों के लिए)
7. तकनीकी भाषण प्रतियोगिता (हिन्दी भाषियों एवं हिंदीत्तर भाषियों के लिए)

हिन्दी पखवाड़ा-2024 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों नें उत्साहपूर्वक भाग लिया। पखवाड़ा के दौरान, लगभग 220 अधिकारियों/संस्थानों ने 14 कार्यक्रमों में भाग लिया और 77 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के विभिन्न राज्यों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिंदी पखवाड़ा का सफल आयोजन किया गया तथा इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

दीर्घा

सर्वोदय कन्या विद्यालय, आरके पुरम सेक्टर 2 और पुष्प विहार सेक्टर 1 के स्कूली छात्रों ने 27 और 28 सितंबर 2024 को जलशक्ति मंत्रालय के आईईसी कार्यक्रम " जल संरक्षण विषय पर - छात्रों के लिए शिक्षा" के तहत इंजीनियरिंग संग्रहालय और राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (एनआरडब्ल्यूक्यूएल), यमुना बेसिन संगठन, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली का दौरा किया।

"एक पेड़ मां के नाम"

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री भूपिंदर सिंह , मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. गंगवार , निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री रवि रंजन , निदेशक (डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in